RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : शनिवार 24 फरवरी 2024 वर्ष 05 अंक 303 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

बांद्रा पश्चिम में बनेगा 165 खाट का कैंसर अस्पताल

मुंबई। कैंसर मरीजों को इलाज की सुविधा के लिए मनपा ने बांद्रा पश्चिम में 165 खाट का कैंसर अस्पताल निर्माण करने का निर्णय लिया है। मनपा के इस निर्णय से मुफ्त कैंसर इलाज चाहने वाले हजारों मरीजों को राहत मिलेगी। भाजपा के स्थानीय विधायक आशीष शेलार ने कैंसर मरीजों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मनपा को बांद्रा पश्चिम में भाभा अस्पताल के सामने मनपा के भूखंड पर एक स्वतंत्र कैंसर अस्पताल बनाने का प्रस्ताव रखा था। मनपा ने आशीष शेलार के प्रस्ताव को मान्य करते हुए 165 खाट का अस्पताल बनाने की मंजूरी दी है मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल के साथ हुई बैठक में मनपा आयुक्त ने कैंसर अस्पताल शुरू करने की हरी झंडी दी। कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए परेल स्थित टाटा अस्पताल और खारघर स्थित टाटा मेमोरियल अस्पताल सहित मनपा का नायर अस्पताल विकिरण चिकित्सा प्रदान करने वाला एकमात्र नागरिक केंद्र है इन अस्पतालों पर बढ़ते भार को कम करने के लिए आशीष शेलार ने बांद्रा में कैसर अस्पताल शुरू करने का प्रस्ताव मनपा को दिया था। बांद्रा में बनने वाले कैंसर अस्पताल में कीमोथेरेपी से लेकर ब्रैकीथेरेपी और रेडिएशन तक और आईसीयू सहित कैंसर का इलाज करने वाला एक अत्याधुनिक अस्पताल बनेगा।

ट्री एक्ट का उल्लंघन करने पर BMC कानूनी मुसीबत में, कार्रवाई की मांग

नागरिक निकाय को कानूनी नोटिस...

बीएमसी पेड़ों को होने वाले नुकसान की परवाह किए बिना खुलेआम रोशनी करके कर रहा है कानून का उल्लंघन ?

मुंबई। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) पेड़ों को होने वाले नुकसान की परवाह किए बिना खुलेआम रोशनी करके कानून का उल्लंघन कर रहा है। पर्यावरण कार्यकर्ता रोहित जोशी ने नागरिक निकाय को एक कानूनी नोटिस भेजा है जिसमें बताया गया है कि पेड़ों की रोशनी महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण और रोकथाम अधिनियम, 1975 की धारा 2 (सी) और 8 का उल्लंघन करती है.वकील रोनिता भट्टाचार्य बेक्टर द्वारा भेजे गए नोटिस में बताया गया है कि रोशनी आदित्य प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश के भी विपरीत है, जो पेड़ों पर बिजली के तारों आदि के उपयोग के खिलाफ था।. साहिल गर्ग बनाम पंजाब राज्य में एनजीटी के आदेशों का उद्धरण, अभिमन्यु राठौड़ बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों को भी कानूनी नोटिस में शामिल किया गया है।

जोशी ने मांग की है कि बीएमसी तुरंत सभी पेड़ों से तार और लाइटें हटा दे, ऐसा न करने पर नगर निकाय के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी। इसी तरह के नोटिस ठाणे और मीरा भयंदर नगर निगमों को भी भेजे गए हैं।अपनी सौंदर्यीकरण योजना के हिस्से के रूप में, बीएमसी और अन्य नागरिक निकायों ने रोशनी की व्यवस्था की है, जिससे हजारों रोशनी हो रही है। कई पेड़, विशेष रूप से मालाबार हिल, वॉकेश्वर, ब्रीच कैंडी और अन्य क्षेत्रों में, पिछले कुछ महीनों से जलाए गए हैं। श्री जोशी ने कहा कि ऐसी अधिकांश लाइटिंग सजावटी प्रतीत होती है, या तो अस्थायी त्योहारों और धार्मिक छुट्टियों के लिए या कुछ स्थानों पर इसे स्थायी आकर्षण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।जोशी ने कहा कि तारों और रोशनी की उपस्थिति पेड़ों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और पक्षियों के लिए उनके घोंसले के निर्माण और निवास के समय बेहद हानिकारक है। तेज रोशनी भी प्रवासी पक्षियों को विचलित कर रही है। नोटिस में यह भी बताया गया है कि, ''पक्षियों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान से पेड़ों पर कीड़ों और कृंतकों पर भी आनुपातिक प्रभाव पड़ता है। इससे पेड़ों के स्वास्थ्य से समझौता हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप प्रभावित पेड़ों के आसपास रहने वाले लोगों को भी परेशानी हो सकती है।''

मुंबई के मीरा रोड पर टी राजा सिंह निकालेंगे शोभा यात्रा,

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सशर्त दी अनुमति

मुंबई : मुंबई से सटे मीरा रोड में पिछले दिनों हिंसा देखने को मिली थी। इस हिंसा के बादपुलिस द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। इस बीच तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने घोषणा की कि वे मीरा रोड में शोभा यात्रा निकालेंगे। इस बीच एआईएमआईएम के विधायक वारिस पठान ने कहा कि वो भी मीरा रोड जाएंगे। मीरा रोड किसी की जागीर नहीं है। जो आना चाहता है आ सकता है। दरअसल टी राजा सिंह ने ऐलान किया था कि वे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर मीरा रोड जाएंगे और शोभा यात्रा निकालेंगे। हालांकि पुलिस की तरफ से उन्हें इस रैली की अनुमति नहीं मिली।

राजा सिंह को कोर्ट ने दी सशर्त अनुमति

बता दें कि राजा सिंह लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो मैसेज के जरिए अपने चाहनें वालों को सूचित कर रहे हैं कि वो मीरा रोड में शोभा यात्रा निकालने वाले हैं। हालांकि इस रैली को मीरा रोड में हुए हिंसा से जोड़ा जा रहा है। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा था, तो उसी दौरान मीरा रोड के नयानगर में हिंसा देखने को मिली थी। बता दें कि राजा सिंह की शोभा यात्रा और रैली मीरा रोड के नयानगर घटनास्थल से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर आयोजित किया जाएगा।

मीरा रोड में शोभा यात्रा निकालेंगे टी राजा सिंह

टी राजा सिंह को शोभा यात्रा निकालने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी है। यह शोभा यात्रा 25 फरवरी शाम 5 बजे निकाली जाएगी। दरअसल राजा सिंह छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म उत्सव को लेकर यह शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक को कड़ी शर्तों के साथ रैली करने की इजाजत दी है। कोर्ट ने राजा सिंह को अनुमति देने के साथ ही कुछ शर्तें भी रख दीं। इन शर्तों के मुताबिक राजा सिंह अपनी रैली के दौरान भड़काऊ भाषण नहीं देंगे। साथ ही पूरी शोभा यात्रा की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।

तुतारी बजाकर, गद्दारों को सिखाओ सबक

नए चुनाव चिन्ह पर शरद पवार गुट का नया नारा

मुंबई : केंद्रीय चुनाव आयोग ने राकां के शरद पवार गुट को तुतारी बजाता हुआ व्यक्ति चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। इस चिन्ह को लेकर पवार गुट के नेता काफी उत्साहित हैं। सीनियर नेता जीतेन्द्र अहवाड ने कहा है कि अब हम तुतारी बजा कर पार्टी के साथ गद्दारी करने वालों को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी महाराष्ट्र की राजनीतिक भूमि पर भीष्माचार्य शरद पवार के साथ यह लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अहवाड ने डिप्टी सीएम अजित पवार का नाम लिए बिना कहा कि वह अपने विरोधियों के खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे।

पवार की मौजूदगी में कार्यक्रम

शरद पवार गुट ने अपने नए चुनाव चिन्ह के अनावरण के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के रायगढ़ किले में शनिवार को भव्य कार्यकर्म का आयोजन किया है। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष शरद पवार की समेत सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इस लांचिंग के साथ पवार की पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए अपने जंग का ऐलान भी कर देगी।

टीजर रिलीज

शरद पवार गुट ने एक्स अकाउंट पर एक टीजर जारी कर पार्टी चिन्ह अनावरण समारोह के बारे में जानकारी दी है। इस टीजर में सांसद अमोल कोल्हे की आवाज है, जो पर्दे पर शिवाजी का किरदार अदा कर चुके हैं। इस टीजर की खास लाइन है कि अब पूरा देश चौंकेगा, शरद पवार के सहयोग से बजेगा विकास का बिगुल। आइए छत्रपति शिवराय की मदद से सही दिशा में तुरही बजाएं।

तीन विकल्प को छोड़ कर अलग चुनाव चिन्ह

राकां प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा हम लोगों ने चुनाव आयोग को तीन विकल्प दिए थे। इनमें बरगद का पेड़, कप प्लेट और सीटी शामिल था।

संपादकीय / लेख

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

तल्खियां हाजिर हैं

नए शपथपत्र, नई उदासियां- करामात यह कि वे बोल रहे हैं। हिमाचल का जायजा लेती विधानसभा सिर्फ बजट का हिसाब नहीं लगा रही, बल्कि देख सुन रही है कि आखिर हो क्या रहा है। सरकार के पूजनीय ढांचे में कर्मचारी समुदाय की खिदमत का अभिप्राय गूंज रहा है। इस प्रदेश में खुशकिस्मत या खुशहाली का आलम देखना हो तो हर सरकार की भाषा में कर्मचारी उद्गार बसते हैं। सदन की पैमाइश में मुद्दों ने पिछले साल की लकीरों में अगले साल की पगडंडियां चुनीं, तो जयराम सरकार से सुक्खू सरकार के आजमाने की तारीखें भी इतिहास बनने लगीं। बजट की बहस के कई निष्कर्ष, कई चिंताएं और कई स्पर्श हैं। इन्हें स्पष्ट करते हुए बजट ने जो लिखा, उसी को उद्धृत करते मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लीव एनकैशमेंट व ग्रेच्युटी के लाभ देने की फरमाइश पूरी कर दी। महिलाओं को मिलने वाली सहायता की गारंटी का मेकअप कुछ इस तरह हुआ कि कुल 2.37 लाख नारियों को अब ग्यारह सौ की जगह 1500 का शगुन मिल जाएगा। पीजी डाक्टरों के भुगतान में 33 के बजाय 40 हजार का भुगतान होगा, जबकि पेन डाउन स्ट्राइक पर आमादा डाक्टरों को अपनी तनख्वाह में एनपीए जोड़ने तक सब्र का कड़वा घूंट पीना होगा। बजट की पेशकश में सरकार की इच्छाशक्ति का प्रदर्शन भले ही कहीं मानदेय में बढ़ोतरी और कहीं नए फामूर्लों के आगाज का सबब बन रहा, लेकिन सरकार के पास कर्मचारियों की इतनी श्रेणियों, कॉडरों और वेतन विसंगतियों का बैगेज खड़ा है कि सुलझते-सुलझाते भी असंतोष का पलड़ा भारी रहता है।

बजट सत्र में मुख्यमंत्री का हर जवाब, लाजवाब नहीं हो सकता और न ही विपक्ष का हर आरोप ईमानदार हो सकता, फिर भी सरकारों की निरंतरता में राजनीति से ऊपर यह प्रदेश बहुत कुछ देखना व सुनना चाहता है। मसलन पिछली सरकारों के शिलान्यास, नए कार्यालयों के लिबास और महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं के स्तंभ ढहने नहीं चाहिए। मंडी में निमार्णाधीन शिवधाम के खाते में बजट की तारीफ आती, तो निश्चित रूप से पर्यटन की इस परियोजना से जनता आशान्वित होती। सदन में पक्ष-प्रतिपक्ष के बीच मुकदमे नहीं हिमाचल के मुकद्दर को एक राह चाहिए और इसलिए सरकार को कोस रही भाजपा भी कम जवाबदेह नहीं। यह प्रदेश सियासी छिलकों से नहीं बना, बल्कि पर्वतीय अस्मिता का जीवंत उदाहरण है, लेकिन बरसात की आपदा ने केंद्र सरकार के रवैये की टीस बढ़ा दी है। कल तक डबल इंजन सरकार की गोटियां खेलती रही मोदी सरकार के सामने हिमाचल की आपदा अपराधी क्यों मानी गई। क्यों प्रदेश के करीब बारह हजार करोड़ के नुकसान की भरपाई में केंद्र के हाथ उदार नहीं हुए। हम भूल नहीं सकते कि आपदा की दरारों में कई गांव ध्वस्त हुए हैं। उजड़े वालों ने तो यह नहीं कहा कि वे भाजपा के खिलाफ थे। राजनीतिक तौर पर भी चुनाव की मत प्रतिशतता में दोनों पार्टियों के बीच अगर स्पष्ट अंतर आया तो यह सीटों की गिनती में आया, वरना पलड़ों में सिर्फ थोड़ी सी शिकायत थी। विपक्ष की तख्तियां, विपक्ष की तल्खियां हाजिर हैं इस उमीद से कि जनता को खबर हो कि कोई उनके लिए मैदान पर था। बहरहाल हिमाचल विधानसभा के तमाम नजारे, बहस के विषय और विधायकों की प्रश्न मंजूषा में यह तो साबित होता है कि असली लोकतंत्र की गाथा में सदन अपना दायित्व निभाता रहा है। बदला है नूर सियासत का भी, वरना साहिब के माथे का पसीना शिकायत न करता। एक संसाधनविहीन राज्य की घोषणाओं में अगर बजट कोशिश कर रहा है या जलशक्ति विभाग के ज्वालामुखी, जयसिंहपुर या चुवाड़ी में डिवीजन कार्यालय खोल रहा है, तो इस हिम्मत को क्या कहें-इस फितरत को क्या कहें। यह दीगर है कि इस बार कुछ कांग्रेसी विधायकों के प्रश्नों में विपक्ष से कहीं ज्यादा बेचैनी है। सदन के शब्दगृह में भाषा का जाल अगर विपक्ष पर फेंका जा रहा है, तो सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेता भी पुचकारे जा रहे हैं। वहां सत्ता के कक्ष में राजिंद्र राणा व सुधीर शर्मा के मायूस चेहरे, मासूम नहीं हैं।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalrokthok
#faisalrokthok

2 फरार बांग्लादेशियों को एनआईए ने दबोचा...
कर्नाटक में छिपे हुए थे, अब तक 14 गिरफ्तार

मुंबई : बांग्लादेश के रास्ते भारत में मानव तस्करी से जुड़े लोगों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है। एनआईए ने बांग्लादेश मानव तस्करी मामले में दो फरार बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी बीते कई दिनों से फरार थे और एनआईए द्वारा इन्हें पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। आखिरकार एनआईए ने इन दोनों फरार बांग्लादेशियों को कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। आइए जानते हैं पूरा मामला। एनआईए ने जानकारी दी है कि बड़े पैमाने पर की गई तलाशी के बाद भगोड़े मोहम्मद साजिद हलदर और इदरीस को कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया है। दोनों भाग रहे थे, और कर्नाटक के आंतरिक सुरक्षा प्रभाग की सहायता से गुरुवार रात को उनका पता लगाया गया और उन्हें पकड़ लिया गया। इसके साथ ही इस मामले कुल गिरफ्तारियों की संख्या 14 हो गई है।

अवैध रूप से भारत में घुस बांग्लादेशी

दरअसल, एनआईए ने बीते साल नवंबर महीने में राष्ट्रव्यापी छापेमारी के बाद एक रैकेट का भंडाफोड़ किया था। एनआईए ने जांच के दौरान पाया कि हलदर और इदरीस भारत-बांग्लादेश सीमा पर बेनापोल के माध्यम से अवैध रूप से भारत में घुस आए थे। हलदर ने बेंगलुरु के राम मूर्ति नगर में के चनासंद्रा में इकाई की स्थापना की भी थी और अपने कार्यों में अन्य बांग्लादेशी नागरिकों को नियुक्त किया था। इदरीस ने 20 से अधिक बांग्लादेशी परिवारों के लिए जमीन पट्टे पर ली थी और तंबू लगाए थे, जिनके बारे में संदेह था कि उनके द्वारा तस्करी की गई थी। इन विवरणों की पुष्टि के लिए जांच जारी है।

भारत में दिलाते थे अवैध एंट्री

एनआईए ने कर्नाटक स्थित कुछ व्यक्तियों के असम, त्रिपुरा और सीमा पार के देशों में मददगारों और तस्करों के साथ संबंध होने के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलने के बाद 7 नवंबर 2023 को मामला दर्ज किया था। आरोपियों को पीड़ितों को फर्जी आधार कार्ड उपलब्ध कराने में भी शामिल पाया गया था। भारत-बांग्लादेश सीमा पर सक्रिय तस्करों पर एनआईए लगातार कार्रवाई जारी रखे हुए है।

कुर्ला नेहरूनगर मे वंचित बहुजन आघाडी कार्यालय पर तोड़क कारवाई के विरोध मे जनआक्रोश मोर्चा

एलवार्ड मनपा अधिकारी हेर्लेकर विधायक मंगेश कुंडलकर के विरोध मे किया सडको पर नारे बाजी

वंचित आघाडी ने बीएमसी से सभी राजनीतिक दलों के अवैध कार्यालय पर बुलडोजर चलाने की मांग

फिरोज सिद्दीकी

मुंबई : कुर्ला नेहरू नगर 19 तारिख को वंचित बहुजन आघाडी के कार्यालय पर हुई तोड़क कारवाई के विरोध मे वंचित आघाडी के पदाधिकारियों,कार्यकार्ताओ ने किया एल वार्ड प्रभाग के कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी । कहा जाता है की शांति पूर्वक आंदोलन कर रहे वंचित आघाडी का आंदोलन तोड़क कारवाई के विरोध मे शांतिपूर्ण तारिक से अपना विरोध जाता1 रहे कार्य कर्ताओ पर जब पोलिस ने जमकर लाठी चार्ज किया तो वंचित आघाडी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता बेकाबू होकर आभद्र भाषा का प्रयोग कर विरोध मे नारे लगाते दिखाई दिये की नीम का पत्ता कडुवा है, सहायक आयुक्त हेर्लेकर, मंगेश कुंडलकर भडुवा है। इतना ही नहीं वार्ड ऑफिसर हेर्लेकर पर गंभीर आरोप लगाते ही कहा की शिवसेना विधायक मंगेश कुंडलकर के भारी दबाव मे आकर हलेर्कार के आदेश पर वंचित आघाडी के कार्यालय पर बीएमसी ने तोड़क कारवाई किया है। उल्लेखनीय तौर पर मोर्चे मे शामिल वंचित की महिला पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओ ने आरोप लगाते हुए कहा की अगर राज्य सरकार, बीएमसी प्रशासन को कार्यालय तोड़ना है तो सबसे पहले मुंबई मे सभी राजनीतिक दलों के कार्यालय पर बीएमसी बुल्डोजर चलवाये। इतना ही नहीं कहा जाता है की महाराष्ट्र प्रदेश भर मे वंचित आघाडी की बढ़ती राजनीतिक ताकत से घबरा कर राज्य की शिंदे सरकार के प्रतिनिधि ऐसी गंदी राजनीतिक करने पर उतारू है। वहीं आगामी होने वाले चुनावों मे। कुर्ला पूर्व विधानसभा क्षेत्र की जनता स्वयं स्थानीय विधायक मंगेश कुंडलकर को घर पर बैठाने का कार्य करेगी।

पालिका मुख्यालय के सामने से कार चोरी

भिवंडी : भिवंडी शहर व ग्रामीण परिसर में एक बार फिर लगातार वाहन चोरी की घटनाओं में वृद्धि होने से वाहन मालिकों ने अपने वाहन की सुरक्षा को लेकर प्रश्न निर्माण हुआ है। शहर के मध्य में स्थित भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका मुख्यालय के सामने, कांग्रेस पार्टी कार्यालय के नीचे से शांतिनगर के रहने वाले इकलाख अंजूम अंसारी की महिन्द्रा कंपनी की एसयूवी 500 कार क्रमांक एम.एच.02 सीएल 5712 को अज्ञात चोर ने पलक झपकते ही चुराकर फरार हो गया है। जिसकी शिकायत उन्होंने शहर पुलिस थाने में दर्ज कराया है। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ कार चोरी का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इकलाख अंसारी ने दोपहर के समय भिवंडी पालिका मुख्यालय के सामने अपनी कार को पार्क कर अन्य कार्य से बाहर चले गये थे और रात 10 बजे के करीब वापस आने पर उनकी कार नहीं मिली।

नवी मुंबई में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी, पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

ठाणे : नवी मुंबई पुलिस ने निवेश पर भारी मुनाफे का लालच देकर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया, आरोपियों ने यह दावा किया कि वह 'एसपीवीएस' नाम की कंपनी से जुड़े हैं और उन्होंने पीड़ितों से उनके माध्यम से शेयरों की खरीद-बिक्री में शामिल होने के लिए कहा। आरोपियों ने वादा किया था कि अगर कोई ग्राहक एक लाख रुपये का निवेश करेगा तो वह एक साल में दोगुना पैसा अर्जित कर लेगा। इसके अलावा उन्होंने लोगों को कई अन्य 'आकर्षक' योजनाएं भी बेचीं। उन्होंने कहा, हालांकि निवेशकों को भारी रकम चुकाने के बाद भी कोई मुनाफा नहीं मिला।

नवी मुंबई पुलिस की नव स्थापित वित्तीय खुफिया ईकाई ने कई शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए सचिन डोंगरे, विकास निकम, भगवान कोंडालकर, दीपाली कोंडालकर और सागर बोराटे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी और महाराष्ट्र जमाकताओं के हितों की सुरक्षा (वित्तीय संस्थानों में) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। उन्होंने बताया कि कंपनी के वाशी और महापे स्थित कार्यालयों पर ताला लगा पाया गया।

हत्या के मामले में सात लोग गिरफ्तार

भिवंडी : भिवंडी शहर में एक नाबालिग युवक की अपहरण कर बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले के मुख्य आरोपी शिवसेना उपशहर प्रमुख कैलास धोत्रे समेत दो अन्य आरोपियों को शहर पुलिस की टीम ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। वही पर इस मामले में फरार चले एक आरोपी को अपराध शाखा की पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या सात हो गई है।

गौरतलब हो कि 14 फरवरी को मामूली विवाद को लेकर दो गटो के बीच झड़प के बाद शिवसेना के उपशहर प्रमुख कैलास धोत्रे उनके बेटे देवा धोज़े और अन्य साथियों ने संकेत भोसले नामक युवक का अपहरण कर लिया और उसे पीट पीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। इस मामले में दोनों पक्षों की शिकायत पर एक दूसरे परस्पर के खिलाफ शहर पुलिस ने केस दर्ज किया था। वही पर संकेत भोसले का इलाज अस्पताल में चल रहा था लेकिन 9 दिन इलाज के बाद उसकी मृत्यु हो गई।

बिल पास करवाने के लिए अधिकारी ने 50 हजार रुपये रिश्वत मांगी... सीबीआई ने जाल बिछाकर ऐसे पकड़ा

मुंबई : रेलवे में माल सप्लाई करने वाली कंपनियों से उनके बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगी जा रही है। इसी तरह का एक मामला पश्चिमी रेलवे में मुंबई सेंट्रल के डीआरएम ऑफिस के एकाउंट्स डिपार्टमेंट से सामने आया है। जहां एक कंपनी द्वारा वेस्टर्न रेलवे को सप्लाई किए गए 4.80 करोड़ रुपये के माल के बिलों की पेमेंट लेने के लिए जब यहां के प्रोसेसिंग ऑफिसर से संपर्क किया गया। तब उन्होंने कंपनी के प्रतिनिधि से बिलों को समय रहते पास करने की एवज में प्रति एक लाख रुपये पर 100 रुपये की रिश्वत मांगी।

जो की करीब 50 हजार रुपये बैठी। इसकी शिकायत सीबीआई से कर दी गई। सीबीआई ने जाल बिछाकर रेलवे के आरोपी अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

सीबीआई ने बताया कि 50 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गुरुवार को वेस्टर्न रेलवे, मुंबई स्थित डीआरएम ऑफिस में तैनात चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट संजय वाघेला को गिरफ्तार किया है। सीबीआई का कहना है कि रेलवे के आरोपी अधिकारी को उस वक्त पकड़ा गया। जब वह 50 हजार रुपये की रिश्वत ले रहे थे। इस मामले में उनके कई ठिकानों पर छापे भी मारे गए हैं। सीबीआई ने बताया कि इस मामले में वेस्टर्न रेलवे के लिए जरूरत के मुताबिक विभिन्न तरह के सामान की सप्लाई करने वाली एक निजी कंपनी ने अपने 4.80 करोड़ रुपये के तीन बिलों की पेमेंट कराने के लिए मुंबई सेंट्रल डीआरएम ऑफिस के अकाउंट डिपार्टमेंट में संपर्क किया। यह कंपनी पश्चिमी रेलवे के लिए नियमित रूप से माल की सप्लाई करती है। आरोप है कि जब इन तीन बिलों के भुगतान के लिए कंपनी के प्रतिनिधि ने यहां आरोपी अधिकारी से संपर्क किया। तब आरोपी ने उनसे कुल पेमेंट में प्रति लाख रुपये पर 100 रुपये रिश्वत के रूप में देने की मांग रखी। रिश्वत की यह रकम आरोपी से 50 हजार रुपये मांगी गई।

मुंबई के झोपड़ पट्टी इलाको में कचरा उठाने के लिए होगा ई रिक्शा का उपयोग

संकरी गालियों में भी जाएगी रिक्शा पर्यावरण को मिलेगा फायदा

मुंबई : मनपा प्रशासन ने झोपड़ पट्टी से निकलने वाले कचरे उठाने के लिए ई रिक्शा का उपयोग करने का निर्णय लिया है। मनपा का कहना है कि ई रिक्शा झोपड़ पट्टी के गलियों तक रिक्शा का सकेगी। ई रिक्शा का उपयोग कचरा उठाने के लिए किए जाने से पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। बता दे कि झोपड़ पट्टी से निकलने वाले कचरे को मनपा ने लोगो के घरों से ही उठाने का निर्णय लिया है। मनपा ने 4 साल के लिए डेढ़ हजार करोड़ का टेंडर निकाला है ।

झोपड़ पट्टी से निकलने वाले कचरे में गीला और सूखा कचरा अलग अलग उठाने के लिए मनपा ने घर घर से कचरा लेने का निर्णय लिया है। लोगो को गिला और सूखा कचरा अलग अलग रखने के लिए

दो प्रकार के डिब्बे भी मनपा मुहैया कराएगी। मनपा का मानना है कि इससे डंपिंग ग्राउंड पर जाने वाले कचरे में कमी आएगी।इतना ही नही मुंबई से कचरे का प्रमाण घटेगा। मनपा ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 'ई-ऑटो रिक्शा' के इस्तेमाल 'एम ईस्ट' वार्ड में विकल्प के रूप में किया जा रहा है। जल्द ही डी वार्ड में भी ई रिक्शा का उपयोग किया जाएगा। मनपा जी दक्षिण वार्ड में इस तरह का उपयोग पहले से ही किया गया था लेकिन उस समय मनपा को ई रिक्शा सी एस आर फंड से मिला था। मनपा अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे ने कहा कि एम और डी वार्ड में सफल प्रयोग होने पर मुंबई के सभी वार्डो में झोपड़ पट्टी इलाको से कचरा उठाने के लिए ई रिक्शा का उपयोग होगा। ई रिक्शा का उपयोग झोपड़ पट्टी के गालीयो में होने से झोपड़ पट्टी से कचरा उठाने की समस्या दूर होगी।

ई-वाहनों से कोई प्रदूषण नहीं फैलता। इसके अलावा रिक्शा बैटरी से चलने के कारण इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जाता है जिससे इन वाहनों से कोई ईंधन दहन प्रक्रिया नहीं होती है। परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है।ई-वाहन चार्जिंग स्टेशनों का उपयोग में आसान विकल्प है।

बांद्रा में 27 फरवरी से 11 मार्च तक 10 प्रतिशत पानी कटौती

मुंबई : मनपा जल विभाग ने 27 फरवरी से 11 मार्च तक बांद्रा पश्चिम इलाके में 10 प्रतिशत पानी कटौती का निर्णय लिया है। जल विभाग के अधिकारी ने बताया कि एच पश्चिम वार्ड में पाली हिल जलाशय के पुराने मुख्य जल पाईपलाइन को बदलने और सुदृढ़ीकरण का कार्य 27 फरवरी को शुरू होगा और यह कार्य 11 मार्च तक चलेगा। इस कारण इस पूरे परिसर में 10 प्रतिशत पानी की कटौती की जाएगी। अधिकारी ने बताया कि इस कार्य के दौरान कांतवाड़ी, शेरली राजन, गजधर बांध क्षेत्र और दंडपाड़ा, दिलीप कुमार जोन, कोल डोंगरी जोन, पाली माला जोन और यूनियन पार्क जोन, खार (पश्चिम), बांद्रा के कुछ क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति में 10 प्रतिशत की कटौती रहेगी। अधिकारी ने कहा कि कार्य पूरा होने के बाद सोमवार 11 मार्च से कटौती वाले क्षेत्रों में दोबारा जलापूर्ति पूर्ववत शुरू हो जायेगी।

चार साल की बच्ची का लैंगिक शोषण...

ठाणे : पड़ोस की रहने वाली एक साढ़े 4 साल की बच्ची का लैंगिक शोषण करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा का आदेश दिया है। दिवा निवासी आरोपी पांडुरंग सुदाम शेलार (47) की पीड़ित बच्ची के परिजनों के साथ उठना बैठना था। बच्ची खेलने के लिए उसके घर गई थी। इसी दौरान उसने बच्ची का लैंगिक शोषण किया। यह मामला प्रकाश में आते ही पूरे परिसर में हड़कंप मच गया था और मामला दर्ज कर शेलर को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की अंतिम सुनवाई जिला न्यायाधीश दिनेश देशमुख की विशेष पास्को अदालत में हुई। पीड़िता के साथ अन्य गवाहों के बयान तथा पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों एवं सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना और 20 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए दंड का आदेश दिया।

मुंबई शहर के सड़कों की बीएमसी 15.49 लाख लीटर पानी से रोजाना कर रही सफाई

मुंबई: मुंबई में बढ़ती पानी की कमी ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को मार्च से 10% पानी की कटौती पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। विडंबना यह है कि इन चिंताओं के बीच, शहर फरवरी की शुरूआत से केवल सड़कों की गहन सफाई और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 310 लाख लीटर पानी खर्च कर रहा है। यह अकेले सड़क की सफाई के लिए निर्धारित लगभग 15.49 लाख लीटर पानी के दैनिक उपयोग को मापता है।मुंबई की जल आपूर्ति मुख्य रूप से नासिक जिले के जलाशयों से होती है, जो अब गर्मियों के आगमन से पहले खतरनाक रूप से खत्म होने के करीब हैं। बताया जाता है कि बीएमसी का हाइड्रोलिक विभाग प्रतिदिन लगभग 659.09 किमी लंबी 422 सड़कों को साफ करने के लिए बोरवेल और सीवेज उपचार संयंत्रों

के पानी का उपयोग कर रहा है। धूल प्रदूषण को दूर करने के लिए, 211 टैंकर और 18 मिस्टिंग मशीनें तैनात की गई हैं, जो अतिरिक्त 59.5 किमी सड़क मार्ग को कवर करती हैं।

शुरूआत में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा धूल को कम करने और समग्र स्वच्छता को बढ़ाने के लिए दिसंबर की शुरूआत में एक साप्ताहिक गतिविधि के रूप में शुरू किया गया था, यह पहल फरवरी से दैनिक कार्य तक बढ़ गई। 25 वार्डों में सुबह 6:30 से दोपहर 2 बजे के बीच चलने वाली इस गतिविधि से प्रतिदिन 175 टन धूल एकत्र होती है।विशेष रूप से, अंधेरी-जुहू खंड में ङ पश्चिम वार्ड इस उद्देश्य के लिए 1.20 लाख लीटर पानी का उपयोग करके चार्ट में सबसे ऊपर है, इसके बाद ङ पूर्व वार्ड है जिसमें अंधेरी पूर्व, जोगेश्वरी पूर्व और विले पार्ले पूर्व शामिल हैं, जहां 1.14 लाख लीटर पानी की खपत होती है।जैसे-जैसे शहर मानसून के मौसम से पहले पानी की एक और कटौती के लिए तैयार हो रहा है, जलाशयों का भंडार हर दिन कम हो रहा है। पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने की लंबे समय से चली आ रही योजनाओं के बावजूद, बीएमसी ने अभी तक व्यवहार्य वैकल्पिक आपूर्ति समाधान लागू नहीं किया है। आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से चल रही परियोजनाओं को साकार होने में अतिरिक्त तीन से चार साल लगने का अनुमान है।

पिछले साल मानसून के देर से आने और समय से पहले चले जाने के कारण शहर में पानी की स्थिति खराब हो गई थी, जिसके परिणामस्वरूप मुंबई की सात आपूर्ति झीलों में केवल 45% स्टॉक था, जो दो वर्षों में सबसे कम था। इस गर्मी में संकट को रोकने के लिए, बीएमसी ने राज्य सरकार से भाटसा और ऊपरी वैतरणा झीलों से आरक्षित भंडार तक पहुंच के लिए याचिका दायर की है, साथ ही अगले महीने से प्रभावी 10% पानी कटौती का प्रस्ताव भी दिया है।ऐतिहासिक रूप से, मुंबई गंभीर जल संकट से जूझ रहा है, 2009, 2014, 2015, 2020, 2022 और 2023 में 15% से 30% तक की कटौती को सहन करते हुए, स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं की तात्कालिकता पर जोर दिया गया है।दीर्घकालिक जल संकट को दूर करने के लिए, नगर पालिका ने मनोरी में एक अलवणीकरण संयंत्र का निर्माण शुरू किया है, जो अपनी स्थापना के बाद से 16 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। प्रति दिन 200 मिलियन लीटर आपूर्ति बढ़ाने वाला यह संयंत्र चार साल में पूरा होने वाला है। इसके अलावा, सीवरेज संयंत्रों को उन्नत करने की योजना में 2,400 मिलियन लीटर उपचारित पानी को सुरक्षित करने का वादा किया गया है, जिसका उद्देश्य गैर-पीने योग्य पानी को द्वितीयक उपयोग के लिए कारखानों में भेजना है।

जेजे के सामने डॉक्टरों का धरना-प्रदर्शन...
सरकार से बातचीत रही बेनतीजा

मुंबई : मुंबई सहित राज्य में दूसरे दिन भी रेजीडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। अपनी मांगों को लेकर मार्ड के रेजीडेंटर डॉक्टरों ने शुक्रवार को जेजे हॉस्पिटल के सामने धरना प्रदर्शन किया। इससे सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों और उनके अभिभावक परेशान हैं। राज्य के प्रमुख सरकारी अस्पताल जेजे में मरीजों और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन मार्ड ने कहा कि हमारी विभिन्न को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की संस्था मार्ड के अध्यक्ष डॉ अभिजीत हेल्गे ने कहा कि हमारे धैर्य की सीमा अब नहीं रही। इसलिए अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए हड़ताल ही एक विकल्प

बचा था। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ 7 फरवरी को जो समझौता हुआ था, उस पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया। इससे डॉक्टरों की चिंता ज्यादा बढ़ गई है। डॉ हेल्गे के अनुसार अब जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।

बदतर स्थिति में मेडिकल स्टूडेंट

धरना दे रहे हड़ताली डॉक्टरों ने कहा कि हम किन मुश्किलों में हॉस्टल में रहते हैं, हर कोई जानता है। जब हमारे रहने की व्यवस्था ही ठीक से नहीं होगी, ऐसे में मरीजों का इलाज कैसे करेंगे। हम एक-एक कमरे में कई स्टूडेंट रहते हैं। काफी मुश्किलों में जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जेजे हॉस्पिटल में मरीजों की परेशानियां बढ़ गई हैं। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं अभी जारी हैं और ज्यादातर मरीज इलाज करा रहे हैं, लेकिन परिजनों का कहना है कि यदि हड़ताल लंबी खिची तो हमें अपने मरीजों को निजी अस्पतालों में ले जाने पर विचार करना पड़ेगा।

बैठक फिर रही बेनतीजा

उधर राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के एमएआरडी प्रतिनिधियों के साथ शुक्रवार को एमईडीडी के मंत्री के साथ बैठक हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बैठक में फिर सिर्फ मौखिक आश्वासन ही दिए गए और मंत्री ने हड़ताल वापस लेने के लिए कहा। लेकिन सेंट्रल मार्ड ने मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने की का फैसला किया है। सेंट्रल मार्ड के अनुसार बार-बार झूठे आश्वासन ही मिलते हैं। हमें इस बार लिखित और ठोस जवाब चाहिए। मार्ड के अनुसार इससे रेजीडेंट डॉक्टरों में अविश्वास की भावना पनप रही है।

धोखाधड़ी करनेवाले शख्स अग्रिम जमानत देने से कोर्ट का इनकार

मुंबई : केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखवत के नाम का दुरुपयोग कर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मशीनें बेचने की आड़ में एक जालसाज कई लोगों से लाखों रुपये ठगने के बाद फरार है। जालसाज अनिरुद्ध सिंह डोडिया के खिलाफ नेरुल पुलिस स्टेशन में एक और मामला दर्ज है। मौजूदा मामले में बेलापुर की जिला एवं सत्र अदालतों द्वारा उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद वह फरार हो गया।धोखाधड़ी करनेवाले अनिरुद्ध सिंह डोडिया के खिलाफ नेरुल पुलिस स्टेशन में एक और मामला दर्ज है। मौजूदा मामले में बेलापुर की जिला एवं सत्र अदालतों द्वारा उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद वह फरार हो गया है। डोडिया ने कथित तौर पर लोगों को उपकरण खरीदने में रुचि जगाने के लिए शेखवात के नाम का इस्तेमाल किया। मामले के शिकायतकताओं में से एक, विजय सिंह, पहली बार अहमदाबाद में एचडीडी मशीन खरीदने गए थे, जहां ब्रोकर जेवेल ओझा से परिचय हुए। ओझा ने उल्लेख किया कि उनके सहयोगी, हेमाक्षीबा डोडिया और अनिरुद्ध डोडिया, अनिरुद्ध सिंह इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं जो भारी मशीनरी का कारोबार करती है।

गोखले ब्रिज को दोबारा खोलने में फिर देरी

मुंबईः कई देरी के बाद, अंधेरी में गोपाल कृष्ण गोखले पुल की एक भुजा अगले सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह तक खुलने की उम्मीद है। हालाँकि, पूरे पुल के उद्घाटन में मई से दिसंबर तक की देरी हो चुकी है।महत्वपूर्ण पूर्व-पश्चिम कनेक्टर के बंद होने से अंधेरी में यातायात संकट बढ़ गया है। पुल का एक किनारा खोलने की समय सीमा कई बार टाली गई। छठी समय सीमा के अनुसार, पुल का आंशिक उद्घाटन 25 फरवरी को निर्धारित किया गया था। हालांकि, समय सीमा समाप्त हो जाएगी क्योंकि कुछ लंबित कार्यों को पूरा होने में सात से 10 दिन लगेंगे।बीजेपी विधायक अमीत साटम ने कहा, ''गोखले ब्रिज के एक हिस्से पर काम लगभग पूरा हो चुका है और एसवी रोड के किनारे पहुंच और मैस्टिक परत को ठीक करने के साथ-साथ फिनिशिंग टच का काम चल रहा है, जिसमें लगभग सात से 10 दिन लग सकते हैं।

जैसे ही काम पूरा हो गया है, पुल को दोनों तरफ से आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा।''विधायक ने आगे कहा कि अगले सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह तक पुल खोल दिया जायेगा. आंशिक उद्घाटन के बाद 2.8 मीटर की ऊंचाई का अवरोधक होगा, जो उस ऊंचाई से ऊपर वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करेगा। उन्होंने कहा कि बाधा 31 मई तक साफ होने की उम्मीद है और उसके बाद सभी ऊंचाई के वाहनों को अनुमति दी जाएगी।इस बीच, दूसरी तरफ का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, जिससे पुल के पूरे उद्घाटन में और देरी होगी। साटम ने पुल के दूसरी तरफ किए गए काम की वर्तमान स्थिति को अपडेट करते हुए कहा, कारखाने में गर्डरों का काम चल रहा है। उनके आने के बाद, गर्डर और पियर्स की लॉन्चिंग शुरू होगी और पूरा होने की लक्षित तिथि 31 दिसंबर, 2024 है।

एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के निधन पर दुख व्यक्त किया

मुंबईः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के निधन पर दुख व्यक्त किया और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने बालासाहेब ठाकरे के लिए एक महान योगदान दिया। ' एक आदर्श महाराष्ट्र का सपना. महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, ''मैंने आज अस्पताल में उनसे मिलने की योजना बनाई थी। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या हुआ। वह बालासाहेब ठाकरे के बहुत करीब थे।

उन्होंने बालासाहेब ठाकरे के आदर्श महाराष्ट्र के दृष्टिकोण में महान योगदान दिया ।'' वह बहुत ही धैर्यवान और सुसंस्कृत व्यक्तित्व थे। महाराष्ट्र की राजनीति और राज्य में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। उनके साथ काम करना और उन्हें जानना सम्मान की बात थी।'' उन्होंने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने कोहिनूर समूह के माध्यम से प्रशिक्षण और काम के अवसर प्रदान किए और वह

बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा के ' कोहिनूर ' थे । डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़णवीस ने कहा, '' मनोहर जोशी राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण राजनेता थे, जिनके व्यक्तित्व की पार्टी लाइनों से परे सराहना की गई। एक मुख्यमंत्री के रूप में राज्य में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई लोगों को प्रेरित किया।'' पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी , महाराष्ट्र में गैर-कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व करने वाले पहले सीएम, ने शुक्रवार सुबह 3 बजे मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह 86 वर्ष के थे। मनोहर जोशी 1995 से 1999 तक मुख्यमंत्री रहे और अविभाजित शिव सेना से राज्य में शीर्ष पद पर आसीन होने वाले पहले नेता थे। वह संसद सदस्य के रूप में भी चुने गए और 2002 से 2004 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार सत्ता में थी।

वसई-विरार मनपा में रहेंगे 29 गांव... हाईकोर्ट ने खारिज की सभी याचिकाएं

वसई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को वसई-विरार मनपा से 29 गांवों को बाहर करने के फैसले पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इससे साफ है कि ये 29 गांव वसई-विरार मनपा में ही रहेंगे। इस बीच, प्रदर्शनकारियों ने यह दावा करते हुए जश्न मनाया कि गांवों को मनपा से बाहर कर 38 दिया गया है, क्योंकि उन्हें मनपा में शामिल करने की अधिसूचना अवैध है। 2009 में तत्कालीन 4 नगर परिषदों और 55 ग्राम पंचायतों को मिलाकर वसई-विरार सिटी कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी। हालांकि 29 गांवों को मनपा में शामिल करने का विरोध किया गया था। इसके विरुद्ध एक बड़ा जन आन्दोलन खड़ा किया गया। इसलिए, तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने 31 मई 2011 को वसई-विरार मनपा से 29 गांवों को बाहर करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया। हालांकि, वसई-विरार नगर पालिका ने सरकार

के इस फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की और स्टे प्राप्त कर लिया। तभी से गांवों को बाहर करने का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन था। इस बीच, राज्य सरकार ने गांवों को बाहर करने के 31 मई 2011 के सरकारी फैसले को रद्द कर दिया और 14 फरवरी 2024 को राज्य सरकार ने एक नई अधिसूचना जारी कर 29 गांवों को नगर पालिका में शामिल कर लिया। राज्य के उप सचिव शंकर जाधव ने नगर निगम से इस संबंध में रिट याचिका (4420) और अन्य संबंधित याचिकाओं को रद्द करने का अनुरोध किया। लिहाजा, गुरुवार को हाईकोर्ट ने नगर पालिका की पिछली स्टे याचिका खारिज कर दी। नई अधिसूचना के अनुसार, वसई विरार मनपा में 29 गांवों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गुरुवार को हाई कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले से पिछले 12 साल से लंबित यह मामला सुलझ गया है। मनपा में गांवों को शामिल करने की राज्य सरकार की 2009 की अधिसूचना कायम है और 2024 में भी गांवों को शामिल करने की नई अधिसूचना जारी कर दी गई है।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४ , मदीना मेंशन, ८१ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सप्प नं 7977408589: Email-editor@rokthoklekhaninews.com